

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 402

मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025/11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहारा सहकारी समितियों में जमा धन की वापसी की स्थिति

†402. श्री राजीव राय:
श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि लाखों ऐसे निवेशक, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा सहकारी समितियों में जमा की है, पिछले 4 से 5 वर्षों से अपनी निवेश राशि की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं;
- (ख) सहारा समूह की विभिन्न सहकारी समितियों में निवेश की गई कुल धनराशि जिन निवेशकों को वापस की गई है, उनकी संख्या कितनी है तथा उन्हें भुगतान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) ऐसे लोगों की संख्या और इन समितियों द्वारा रोके गए धन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या बड़ी संख्या में निवेशकों को अभी भी उनकी जमा राशि वापस नहीं की गई है;
- (ङ) यदि हां, तो निवेशकों की संख्या और संवितरित की जाने वाली कुल राशि का ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार का इन सभी निवेशकों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से धन वापस करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (छ) क्या सरकार का निवेशकों को ब्याज या मुआवजे के साथ उनका धन वापस दिलाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (छ): सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका (सि) सं.191/2022 (पिनाक पाणी मोहंती बनाम् भारत संघ और अन्य) में दायर अंतर्वर्ती आवेदन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 को अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया कि:

"(i) Out of the total amount of Rs. 24,979.67 Crores lying in the "Sahara-SEBI Refund Account", Rs. 5000 Crores be transferred to the Central Registrar of Cooperative Societies, who, in turn, shall disburse the same against the legitimate dues of the depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies, which shall be paid to the genuine depositors in the most transparent manner and on proper identification and

on submitting proof of their deposits and proof of their claims and to be deposited in their respective bank accounts directly.

(ii) The disbursement shall be supervised and monitored by Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court with the able assistance of Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate, who is appointed as Amicus Curiae to assist Justice R. Subhash Reddy as well as the Central Registrar of Cooperative Societies in disbursing the amount to the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. The manner and modalities for making the payment is to be worked out by the Central Registrar of Cooperative Societies in consultation with Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court and Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate."

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की चार बहुराज्य सहकारी समितियों, अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके वैध धनराशि के रिफंड दावे प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.07.2023 को "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" <https://mocrefund.crcs.gov.in> का शुभारंभ किया गया है। संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज़रहित है जिसे न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल, न्यायमित्र की सहायता से किया जा रहा है।

इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को उचित पहचान और जमाराशि के साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत पारदर्शी रीति से प्रोसेस किया जा रहा है। वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से 50,000/- रुपये तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है। इसके अलावा, पोर्टल पर किसी जमाकर्ता के प्राप्त आवेदन में किसी कमी की दशा में उन्हें इन कमियों से अवगत कराया जा रहा है और उन्हें दिनांक 15.11.2023 को लॉन्च हो चुकी "री-सबमिशन पोर्टल" के माध्यम से अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत करने की सूचना दी जा रही है। संवितरण की यह प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया द्वारा मार्गदर्शित होती है। सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए मंत्रालय सभी संभावी कदम उठा रहा है। दिनांक 25.11.2025 तक प्राप्त आवेदनों और भुगतान का राज्य-वार ब्योरा संलग्न है।

दिनांक 25.11.2025 की स्थिति के अनुसार, सहारा समूह की सहकारी समितियों के 1,41,07,105 जमाकर्ताओं में से सहारा रिफंड पोर्टल और री-सबमिशन पोर्टल पर आवेदन करने वाले 35,24,966 जमाकर्ताओं को 6,841.86 करोड़ रुपये की धनराशि का संवितरण किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को संवितरण करने की समय-सीमा को दिनांक 31.12.2026 तक बढ़ा दिया है।
